

मराठा संघर्ष योद्धा जरांगे का तूफान मुंबई की सीमा पर!

देश की आर्थिक राजधानी
हाई अलर्ट पर!

आजाद मैदान को मिला सैन्य छावनी
का रूप, जरांगे की ओर से पुलिस को आश्वासन पत्र

जमीर काजी कि रिपोर्ट
मुंबई:

उच्च न्यायालय और सरकार के विरोध को नजरअंदाज करते हुए मराठा आरक्षण की मांग के लिए आंदोलक मनोज जरांगे अपने सहयोगियों के साथ कल (शुक्रवार) को राज्य की राजधानी में दस्तक देने जा रहे हैं। गुरुवार मध्यरात्रि को वे वाहनों के काफिले के साथ देश की आर्थिक राजधानी की सीमा पर पहुंच गए हैं, जिसके चलते पूरे मुंबई और नवी मुंबई क्षेत्र को 'हाई अलर्ट' पर रखा गया है।

राज्य भर से आंदोलकों की भीड़ मुंबई की ओर कूच कर रही है, जिसके कारण गुरुवार को हाईवे पर भारी भीड़ और वाहनों के काफिले के चलते यातायात व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो गई। आजाद मैदान, जहां धरना देने की योजना है, और मार्च के रास्तों पर कड़ा बंदोबस्त किया गया है, जिससे यह स्थान सैन्य छावनी जैसा दिख रहा है।

आंदोलन के लिए मुंबई पुलिस ने २९ अगस्त को सुबह ९ बजे से शाम ६ बजे तक की अनुमति दी है। हालांकि, संघर्ष योद्धा जरांगे ने मांग पूरी होने तक अनिश्चितकालीन धरना देने का संकल्प दोहराया है। इससे मराठा आंदोलकों और पुलिस के बीच बड़े संघर्ष की



आशंका है। इस पृष्ठभूमि में मुंबई में रेड अलर्ट घोषित किया गया है। आजाद मैदान के आसपास ही नहीं, बल्कि पूरे शहर में करीब ५,००० पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। साथ ही, राज्य सुरक्षा बल और सीआरपीएफ की टुकड़ियों को भी बुलाया गया है। जरांगे के आंदोलन के लिए ५,००० आंदोलकों को आजाद मैदान में अनुमति दी गई है, लेकिन इससे कई गुना अधिक आंदोलकों के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। उन्हें शहर में कोई रैली या जुलूस निकालने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही, आंदोलन के दौरान माइक और लाउडस्पीकर का उपयोग भी नहीं किया जा सकेगा। केवल



महत्वपूर्ण व्यक्तियों के साथ पांच वाहनों को ही आजाद मैदान तक प्रवेश की अनुमति होगी। इसके अलावा, मुंबई में आने वाले वाहनों को वाडी बंदर जंक्शन पर निर्धारित स्थान पर ही पार्क करना होगा। शाम ६ बजे के बाद सभी आंदोलकों को आजाद मैदान खाली करना होगा। ऐसी शर्तें जरांगे के आंदोलन के लिए तय की गई हैं। जरांगे-पाटिल की ओर से पुलिस को आश्वासन पत्र शुक्रवार के आंदोलन के लिए जरांगे-पाटिल ने गुरुवार को पुलिस को आश्वासन पत्र सौंपा है, जिसमें २० विभिन्न आश्वासन दिए गए हैं। पुलिस ने आंदोलन के लिए कई

शर्तें लगाई हैं, लेकिन केवल एक दिन के लिए आंदोलन की अनुमति दी गई है। इस पर जरांगे-पाटिल ने नाराजगी व्यक्त की है। साथ ही, आंदोलन के समय को लेकर भी उन्होंने आपत्ति जताई है।

ये हैं आश्वासन: आंदोलन की अनुमति की मूल प्रति साथ रखी जाएगी। पुलिस के साथ नियमित संपर्क के लिए पांडुरंग मारक को जिम्मेदार व्यक्ति नियुक्त किया जाएगा। स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं से चर्चा कर आंदोलन स्थल पर पीने के पानी और चिकित्सा सहायता की पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी।

यातायात में बाधा नहीं डाली जाएगी। पार्किंग स्थल का उपयोग और यातायात नियमों का पालन किया जाएगा।

आंदोलन में शामिल होने वाले व्यक्तियों की संख्या सीमित रखी जाएगी और इसमें वृद्धि नहीं होगी।

आंदोलन स्थल पर पर्याप्त स्वयंसेवक तैनात किए जाएंगे और उनकी सूची पुलिस को दी जाएगी।

आंदोलन केवल निर्धारित स्थान पर ही होगा।

सुबह ९:३० से शाम ५:३० तक आंदोलन होगा, इसका आयोजक सुनिश्चित करेंगे।

बैनर और झंडों के लिए २ फीट से अधिक लंबी छड़ियों का उपयोग नहीं किया जाएगा। बैनर का आकार ६ फीट या उससे कम होगा। सहभागी व्यक्ति झंडे या बैनर केवल आंदोलन के उद्देश्य के लिए ही रखेंगे।

आंदोलन में शामिल व्यक्ति लाठियां, अग्निशस्त्र, भाले, तलवारें या अन्य वस्तुएं साथ नहीं रखेंगे, इसका आयोजक सुनिश्चित करेंगे।

कोई भी व्यक्ति उत्तेजक भाषण या धर्म, जाति, स्थान, जन्म, निवास, भाषा आदि के आधार पर शत्रुता पैदा करने वाली भाषा का उपयोग नहीं करेगा।

सहभागी व्यक्ति पुलिस के कानूनी निर्देशों का तुरंत पालन करेंगे।

सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान, सरकारी कर्मचारियों पर हमला, उनके कर्तव्यों में बाधा, आगजनी आदि कोई भी कृत्य सहभागी व्यक्ति नहीं करेंगे।

किसी भी धर्म या वर्ग के व्यक्ति का अपमान करने के उद्देश्य से कोई धार्मिक स्थल या किसी वर्ग द्वारा पवित्र मानी जाने वाली वस्तु को नष्ट या अपवित्र नहीं किया जाएगा।

आंदोलन स्थल से कूच करने की मुद्रा में नहीं जाया जाएगा।

किसी भी प्रकार के कागजात, किताबें या चित्र नहीं जलाए जाएंगे। खाना पकाने या कचरा फैलाने को प्रोत्साहन नहीं दिया जाएगा।

बिना अनुमति लाउडस्पीकर का उपयोग नहीं किया जाएगा। अनुमति के बाद केवल सुबह ९:३० से शाम ५:३० तक इसका उपयोग होगा।

वाहन या कोई पक्षी-जानवर आंदोलन स्थल पर नहीं लाए जाएंगे।

अनुयायियों को नियंत्रण में रखने की जिम्मेदारी मेरी होगी, और इसमें विफल रहने पर मेरे और अन्य आयोजकों पर मुकदमा दर्ज किया जाए। आश्वासन पत्र के मार्गदर्शक सिद्धांतों का पालन और पुलिस को सहयोग किया जाएगा।

महाराष्ट्र की स्थिति बिहार जैसी हो जाएगी

पुणे, (रिपोर्टर):

पुणे में गौरक्षकों द्वारा विधायक सदाभाऊ खोत के साथ किए गए दुर्व्यवहार की उपमुख्यमंत्री अजित पवार की राष्ट्रवादी पार्टी के विधायक इंदिरा नायकवडी ने निंदा की है। गौरक्षा के नाम पर महाराष्ट्र में तोड़फोड़ का धंधा चल रहा है और महाराष्ट्र बिहार की तरह होने की राह पर है, ऐसी आलोचना नायकवडी ने की। इस मुद्दे पर अजित पवार की राष्ट्रवादी पार्टी के विधायक इंदिरा नायकवडी ने सरकार को ही आड़े हाथों लिया। उन्होंने मांग की कि गौरक्षा के नाम पर समाज विरोधी कृत्य करने वालों पर 'मकोका' (महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट) के तहत कार्रवाई होनी चाहिए।

गौरक्षा के नाम पर समाज विरोधी कृत्य करने वालों पर मकोका लगाएं-विधायक नायकवडी

पिछले कुछ दिनों से राज्य में पशुधन की

दुलाई करने वालों का पीछा कर गौरक्षकों द्वारा कानून को अपने हाथ में लेने की बात सामने आई है। गौरक्षकों ने किसानों को लूटने का नया धंधा शुरू किया है। ऐसी विकृत मानसिकता के गौरक्षकों के कारण महाराष्ट्र बिहार जैसा होने की राह पर है। नायकवडी ने कहा कि आगामी विधानसभा सत्र में इस मुद्दे को निश्चित रूप से उठाया जाएगा।



दूसरी ओर, पुणे में गौरक्षकों द्वारा विधायक सदाभाऊ खोत के साथ धक्का-मुक्की की गई। यह घटना पुणे के द्वारकाधीश गौशाला के पास हुई। फुरसंगी में द्वारकादास गौशाला में विधायक सदाभाऊ खोत अपने कार्यकर्ताओं के साथ गए थे। उस समय कुछ गौरक्षकों ने उनके साथ धक्का-मुक्की की। इस मामले पर बोलते हुए सदाभाऊ खोत ने कहा कि राज्य में गोवंश कानून का हवाला देकर जब किसान दूध देने वाले पशुओं

को बेचने जाते हैं, तब उनकी पिटाई की जाती है और उनके पशुओं को जबरदस्ती छीन लिया जाता है। पुलिस स्टेशन में वे पशु ले जाए जाने के बाद उन्हें गौशालाओं में भेजा जाता है। इसके बाद प्रति दिन २०० से ५०० रुपये का शुल्क वसूला जाता है। अगर इस मामले का फैसला एक या डेढ़ साल बाद आता है, तो किसान ज़ुर्माना नहीं भर पाता और वह अपने पशुओं को वापस नहीं ले पाता। सतारा के कोरेगांव तालुका की १० में से और उनके ११ बछड़ों को पुणे की द्वारकाधीश गौशाला में लाया गया था। मैं यह देखने गया था कि वे मैंसे वहां हैं या नहीं, लेकिन गौरक्षकों ने इसका विरोध किया।

MAK TAB
PHARMACEUTICAL

REQUIRED PHARMACIST

- Beed
- Licensed Pharmacist (for retail pharmacy setup)

Please connect on WhatsApp

9754221866

BUSINESS COLLABORATION

- Doctors & Distributors – start your own brand with our Third-Party Manufacturing Support
- Complete guidance for Retail Pharmacy Setup

Amjad Khan - 9754221866



नौफल युनानी सेंटर
नौफल हरबल फारमेसी



बतारीख: 31 अगस्त 2025, बरोज इतवार
सुबह 11 बजे, बमुकाम डॉ.मुबारक कॅपिटल,बाशीं नाका,
मोमीन पुरा बायपास कॉर्नर,बीड



बदस्त
डॉ.शय्यक इक्ष्वाव अहेमद

(प्रिंसीपल युनुस फजलानी युनानी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल,कनड,औरंगाबाद)

दुआ बदस्त

हजरत मौलाना मुफ्ती मुहम्मद आरिफ साहब आरफी (इमाम एक मीनार मस्जिद,बीड)

हजरत मौलाना मुफ्ती मुहम्मद जावेद साहब हुसैनी (सवर मुदरिस सदरसा दारुलउलूम बीड)

हजरत मौलाना अमीन साहब रशीदी (इमाम मरकज मस्जिद,बीड)

हजरत हाफिज निसार साहब

महेमानाने खुसूसी

डॉ.हकीम चाँद पटेल साहब (DAMS) जनाब अहेमद साहब उर्फ शहिंशाह

डॉ.शेख रईस साहब डॉ.शेख मुबारक साहब (BHMS,CCH,DAMU.)

डॉ.निखत एम.शेख (BUMS EX-UNANI MEDICAL OFFICER CIVIL HOSPITAL,BEED.)

मिजजाजिष्ठ

हकीम मोहम्मद वसीम खान प्रोफ़ा.नोफल हरबल फार्मेसी
8886884202 / 9966554202

हर महीने के 1 तारीख से 8 तारीख तक हकीम साहब बीड के सेंटर पर रहेंगे
सुबह 10:30 से दोपहर 3 बजे तक शाम में 7 बजे से 10 बजे तक

DECENT: 9175 566 266

उर्दू दैनिक तामीर के २५ वे साल में क़दम रखने पर एक और पेशकश

जरांगे के आंदोलन के पीछे राजनीतिक समर्थन: मुख्यमंत्रीने विपक्ष पर साधा निशाना

जमीर काजी मुंबई:

लोकतांत्रिक तरीके से और न्यायालय द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार आंदोलन करने का किसी को विरोध नहीं है। लेकिन इस आंदोलन के लिए संसाधन जुटाने वाले कौन हैं? यह देखने को मिल रहा है। कुछ राजनीतिक दल इनके कंधों पर बंदूक रखकर अपना फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इससे उनका नुकसान होगा, फायदा नहीं, ऐसा इशारा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को विपक्ष को दिया।

गणेशोत्सव की धूमधाम के बीच मनोज जरांगे-पाटिल के नेतृत्व में शुक्रवार को आजाद मैदान में मोर्चा पहुंचने वाला है, जिसके चलते मुंबई में अभूतपूर्व स्थिति

पैदा हो गई है। इस पृष्ठभूमि में पत्रकारों से बात करते हुए फडणवीस ने कहा, पहले क्या हुआ, यह आप सभी ने देखा है। सरकार मराठा और ओबीसी समाज के साथ अन्याय नहीं होने देगी। मराठा समाज को आरक्षण दिया गया है, जो कोर्ट में भी टिक गया है। किसी का भी आरक्षण छीना नहीं जाएगा। लोकतंत्र के दायरे से बाहर कोई नहीं जाना चाहिए, यही हमारी इच्छा है।

उन्होंने कहा कि मराठा समाज के नेताओं को अध्ययन कर मांगें रखनी चाहिए। आंदोलन के लिए जो नियम-कायदे बनाए गए हैं, अगर उनके अनुसार आंदोलन होता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने आगे कहा, हमें पता है कि ओबीसी में करीब

साढ़े तीन सौ जातियां शामिल हैं। अगर हम मेडिकल प्रवेश की बात करें, तो ओबीसी



का कट-ऑफ ड्रइउ से ऊपर है, और ड्रइउ का कट-ऑफ एथड से ऊपर है। इसलिए इस मांग से कितना भला होगा,

मुझे नहीं पता। अगर आंकड़ों को ठीक से देखा जाए, तो मराठा समाज के हित में क्या है, यह समझ में आएगा।

फडणवीस ने कहा, इस आंदोलन के लिए संसाधन कहां से आ रहे हैं, यह स्पष्ट है। लेकिन ठीक है। मेरा कहना है कि हमारे लिए यह आंदोलन राजनीतिक नहीं है, हम इसे सामाजिक दृष्टिकोण से देख रहे हैं। लेकिन कुछ राजनीतिक दल इसका उपयोग कर रहे हैं। इससे किसी का भला नहीं होगा। मराठा समाज की भी जिम्मेदारी है कि वे अपने हित का अध्ययन कर मांगें रखें। एक बात सही है कि ड्रइउ आरक्षण में राजनीतिक आरक्षण नहीं मिलेगा। अगर राजनीतिक आरक्षण उद्देश्य है, तो बात अलग है।

लेकिन अगर सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन की लड़ाई है, नौकरी और प्रवेश की मांग है, तो कम से कम कुछ विचारकों को इस पर विचार करना चाहिए।

जरांगे के मुंबई पहुंचने पर होगी चर्चा: विखे-पाटिल

मराठा आरक्षण पर राज्य सरकार की उपसमिति के अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे-पाटिल ने कहा, हम आंदोलकों के साथ कभी भी चर्चा करने को तैयार हैं। जरांगे-पाटिल मुंबई आना चाहते हैं, तो हम उनके साथ मुंबई में सकारात्मक चर्चा करेंगे।

आंदोलन को इन विधायकों-सांसदों का समर्थन

इस आंदोलन को चार सत्ताधारी विधायकों का समर्थन प्राप्त है, जिनमें

राष्ट्रवादी (अजित पवार गुट) के विधायक प्रकाश सोलंके, विजयसिंह पंडित, राजू नवधरे और शिंदे गुट के विलास भुमरे शामिल हैं। वहीं, विपक्षी दलों के तीन सांसदों और दो विधायकों ने आंदोलन को समर्थन दिया है। इनमें राष्ट्रवादी (शरद पवार गुट) के सांसद बजरंग सोनवणे, विधायक संदीप क्षीरसागर, शिवसेना (ठाकरे गुट) के सांसद ओमराजे निंबाळकर, सांसद संजय जाधव और विधायक कैलास पाटील शामिल हैं। सोनवणे और क्षीरसागर आंदोलन में शामिल हो चुके हैं, जबकि सोलंके शामिल होने वाले हैं। विधायक पंडित ने अपने निर्वाचन क्षेत्र में आंदोलन के समर्थन में पोस्टर लगाए हैं।

तय्यबनगर में अमरसिंह पंडित और विधायक विजयसिंह पंडित के प्रयासों से पी.टी.आर. और घरकुल का रास्ता सुगम

काजी अमान / गेवराई

राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रदेश महासचिव एवं पूर्व विधायक अमरसिंह पंडित और विधायक विजयसिंह पंडित के प्रयासों तथा महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष समीर काजी की सकारात्मक भूमिका के चलते गेवराई के तय्यबनगर क्षेत्र सहित मराठवाड़ा में वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर बसे नागरिकों के पी.टी.आर. (प्रांणटी टैक्स रसीद) और घरकुल का रास्ता अब आसान हो गया है। यह जानकारी राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस के पदाधिकारी वसीम फ़ारुकी ने दी।



पी.टी.आर. उपलब्ध कराने का कानूनी रास्ता निकाला जाएगा।

कुछ माह पूर्व विकासोन्मुख पूर्व विधायक अमरसिंह पंडित और गेवराई विधानसभा क्षेत्र के युवा, कर्मठ एवं सक्रिय विधायक विजयसिंह पंडित की अध्यक्षता में तथा अल्पसंख्यक समाज के विकास के लिए समर्पित, राज्यमंत्री पद का दर्जा प्राप्त वक्फ बोर्ड अध्यक्ष समीर काजी की प्रमुख उपस्थिति में गेवराई नगर परिषद में बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि गेवराई शहर के वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर बसे ५९० परिवारों को घरकुल उपलब्ध कराने के लिए

वक्फ बोर्ड का नाहरकत प्रमाणपत्र और भाड़ेपट्टा आवश्यक है और इस पर शीघ्र कार्यवाही की जाएगी।

वक्फ बोर्ड अध्यक्ष समीर काजी की सकारात्मक भूमिका के कारण केवल तय्यबनगर ही नहीं बल्कि पूरे मराठवाड़ा क्षेत्र में वक्फ बोर्ड के किरायेदारों को शासन की घरकुल योजना का लाभ मिलेगा। निर्माण कार्य के लिए नाहरकत प्रमाणपत्र उपलब्ध कराने हेतु कानूनी पहलुओं की जांच कर वक्फ बोर्ड हर संभव सहयोग करेगा, ऐसा आश्वासन अध्यक्ष समीर काजी ने दिया।

राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस के पदाधिकारी वसीम फ़ारुकी की लगातार की गई पहल को सफलता मिली है और तय्यबनगर क्षेत्र में वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर पी.टी.आर. और घरकुल का रास्ता अब सुगम हो गया है।

सरकारने तुरंत मराठा आरक्षण की घोषणा करनी चाहिए : हर्षवर्धन सपकाळ

- जमीर काजी

मुंबई :

सरकार चाहे तो पाँच मिनट में

मराठा आरक्षण का प्रश्न हल हो सकता है, लेकिन वह कर नहीं रही। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राजधर्म का पालन करते हुए तुरंत घोषणा करनी चाहिए और दिल्ली जाकर आरक्षण की ५०% सीमा हटानी चाहिए। ऐसी माँग कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ ने की है।

टिळक भवन में बुधवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए उन्होंने कहा कि, मराठा समाज को आरक्षण मिले इसके लिए मनोज जरांगे पाटिल समाज सहित मुंबई पहुँच रहे थे, लेकिन सरकार ने इस आंदोलन में अड़चन डालने का प्रयास किया। अब केवल एक दिन की अनुमति देना हास्यास्पद है, जबकि तीन महीने पहले ही आंदोलन की घोषणा की गई थी। तो सरकार इतने दिनों से सो रही थी क्या?

काँग्रेस-आघाड़ी सरकार ने मराठा समाज को आरक्षण दिया था। महाराष्ट्र विधानमंडल में भाजपा-युति सरकार के समय मराठा आरक्षण का ठराव पास हुआ, जिसे काँग्रेस पार्टी ने समर्थन दिया था। सत्ता में आते ही ७ दिन में मराठा आरक्षण देंगे ऐसा गड़गड़ाता ऐलान देवेंद्र

फडणवीस ने किया था, उसका क्या हुआ? धनगर समाज को मंत्रिमंडल की पहली ही बैठक में आरक्षण देने का वादा फडणवीस ने किया था, उसका क्या हुआ?

‘सागर’ बंगले पर मंथन कर अमृत पीकर विष समाज और विपक्ष पर फेंकने का पाप फडणवीस और भाजपा कर रहे हैं, ऐसा आरोप करते हुए सपकाळ ने कहा कि फूट डालो और राज करो की अंग्रेज़ों की नीति पर भाजपा और फडणवीस काम कर रहे हैं। जब एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने थे, तब नवी मुंबई में छत्रपति शिवाजी

महाराज की प्रतिमा के सामने शपथ लेकर गुलाल उड़ाया था, उसका क्या हुआ? इन सवालों का जवाब देना चाहिए। आज जो तीन दल सत्ता में हैं, वही उस समय भी सत्ता में थे। आरक्षण पर जाति आधारित जनगणना ही रामबाण उपाय है - यह लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने स्पष्ट किया है और उसके लिए वे लगातार आग्रह भी कर रहे हैं। काँग्रेस-शासित तेलंगाना और कर्नाटक में जाति आधारित जनगणना की जा चुकी है। भाजपा सरकार में यदि इच्छाशक्ति है तो उन्हें भी जाति आधारित जनगणना कर मराठा आरक्षण का प्रश्न हल करना चाहिए।



माटेगांव में शराबबंदी का ग्राम पंचायत प्रस्ताव

सरपंच श्रीमती शीतल आरबड ने लिया पहल



काजी अमान/गेवराई

गेवराई तालुका के माटेगांव ग्राम पंचायत की सरपंच श्रीमती शीतल ज्ञानेश्वर आरबड की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में माटेगांव में शराब की बिक्री और शराबबंदी का निर्णय लिया गया है। इस बीच, ग्राम पंचायत के इस निर्णय का क्षेत्र में स्वागत किया जा रहा है।

इस संबंध में विस्तृत जानकारी इस प्रकार है: गेवराई तालुका के माटेगांव में जिला परिषद स्कूल, मंदिर और बस स्टैंड के आसपास अवैध शराब बिक्री के कारण लोग नशे की लत में पड़ रहे हैं, जिससे सार्वजनिक शांति भंग हो रही है और स्कूल के बच्चों और महिलाओं को परेशानी हो रही है। इस समस्या को देखते हुए सरपंच श्रीमती शीतल ज्ञानेश्वर आरबड ने शराबबंदी के लिए पहल की। दिनांक २२ फरवरी को सरपंच श्रीमती शीतल आरबड की अध्यक्षता में आयोजित ग्राम सभा में शराबबंदी का प्रस्ताव पारित किया गया। इस दौरान शरद आशाजी शिंदे ने सभा में विषय रखा कि माटेगांव और आसपास के क्षेत्र में स्कूल, मंदिर और बस स्टैंड के पास अवैध शराब बिक्री के कारण स्कूल के बच्चों और गाँव की महिलाओं को परेशानी

हो रही है। साथ ही, अवैध शराब बिक्री और शराब पीने के कारण लोग नशे की लत में पड़ रहे हैं, जिससे गाँव में निम्नलिखित समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं। यदि गाँव में अवैध शराब बिक्री को स्थायी रूप से बंद किया जाए, तो शराब के कारण होने वाले दुष्परिणामों को रोका जा सकता है। इस पर सरपंच, उपसरपंच और सभी ग्रामवासियों के बीच विस्तृत चर्चा हुई, और सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया। इस अवसर पर सरपंच श्रीमती शीतल आरबड, उपसरपंच श्रीमती गीता शहादेव यादव, ज्ञानेश्वर आरबड, ग्राम सेवक पी.आर. घाडगे के साथ-साथ सभी ग्राम पंचायत सदस्य उपस्थित थे।

ग्राम पंचायत की ओर से शराबबंदी प्रस्ताव और निवेदन चकलंबा पुलिस स्टेशन के सहायक पुलिस निरीक्षक संदीप पाटील को सौंपा गया है। माटेगांव ग्राम पंचायत के इस निर्णय का क्षेत्र में स्वागत किया जा रहा है। इस अवसर पर महादेव कर्डिले, भागवत जंगले, योगेश गावडे, अजय टेकाले, अभिजीत चव्हाण, अर्जुन घाडगे, हकीम शेख, सचिन जाधव, दादासाहेब यादव, विक्रम गरुड, गोविंदराव चहाण, सुरेश कदम सहित बड़ी संख्या में ग्रामवासी उपस्थित थे।

बीड़ में बारिश से हाहाकार: नगर पालिका की लापरवाही उजागर



बीड़, (सय्यद इरफान) बीड़ शहर में हुई एक घंटे की जोरदार बारिश ने नगर पालिका प्रशासन की लापरवाही को उजागर कर दिया। शुक्रवार को हुई इस मुसलाधार बारिश के बाद जालना रोड सहित बशीर गज, कारंजा और जुना बाजार में जल जैसा इलाकों में पानी भर गया। नालों का पानी सीधे सड़कों पर बह

निकला और कई घरों में घुस गया, जिसके चलते फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक सामान और अनाज को भारी नुकसान हुआ। स्थानीय नागरिकों ने आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि, हर साल बारिश के मौसम में हमें यही स्थिति झेलनी पड़ती है। समय पर टैक्स भरने के बावजूद बुनियादी सुविधाएं नहीं मिलतीं। प्रशासन से सिर्फ

आश्वासन ही मिलते हैं। दुकानदार और नागरिकों को भारी नुकसान पानी घरों और दुकानों में घुस जाने से रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुएं खराब हो गईं। छोटे व्यापारियों को भी बड़ा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। बशीर गज, कारंजा और जुना बाजार में जल जैसा इलाकों में पानी भर गया। नालों का पानी सीधे सड़कों पर बह

पूरी रात घरों से पानी बाहर निकालने की मशकत करनी पड़ी। कई जगहों पर पानी घंटों तक जमा रहा, जिसके कारण लोगों के लिए घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया। नागरिकों का आरोप रहवासियों का कहना है कि अगर समय से नाले और गटरों की सफाई कराई गई होती तो हालात इतने खराब नहीं होते।

नगर पालिका के गैरजिम्मेदार रवैये के कारण ही आज नागरिकों को इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन से मांग नागरिकों ने प्रशासन से मांग की है कि तुरंत नालों की सफाई कर पानी निकासी की उचित व्यवस्था की जाए। अन्यथा वे सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने को

मजबूर होंगे। बीड़ शहर में बार-बार पानी भरने की समस्या आती है, लेकिन नगर पालिका की ओर से ठोस कदम नहीं उठाए जाते। हर साल केवल आश्वासन दिए जाते हैं, मगर लोगों की परेशानी जस की तस बनी रहती है। अगर इस बार भी प्रशासन ने गंभीरता नहीं दिखाई, तो जनता का गुस्सा और बढ़कना तय है।

दैनिक भारत की तामीर अखबार के मालिक, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक काजी मखदूम शफीउद्दीन ने आरएम प्रिंटरर्स, बारशी रोड, बीड 431122 महाराष्ट्र में मुद्रित कर के दैनिक तामीर, नगर परिषद परिसर, बशीर गंज, बीड, महाराष्ट्र कार्यालय से प्रकाशित किया है। मोबाइल : 9270574444 ईमेल : hinditameer@gmail.com वेबसाइट : www.dailytameer.com daily Bharat ki tameer newspaper owner printer publisher editor Quazi makhdoom shafuiddin has printed at RM printers barshi road beed 431122 Maharashtra. Mobile : 9270574444 Email : hinditameer@gmail.com Website : www.dailytameer.com